भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2942
दिनांक 13.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

एक्ट ईस्ट नीति

2942. श्री जोगेन मोहन:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत असम को लाभान्वित करने वाली नई पहल की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम को दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए व्यापारिक प्रवेश-द्वार के रूप में विकसित किए जाने का विचार है; और

(घ) वर्तमान में कौन-कौन सी प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(**श्री पबित्र मार्गेरिटा**)

(क से घ) असम सहित भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में निहित है, जो दक्षिण पूर्व एशिया हेतु देश के रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह क्षेत्र आसियान के लिए सबसे कम दूरी की ओवरलैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है तथा व्यापार, परिवहन, पर्यटन, ऊर्जा सहयोग और लोगों के आपसी आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन, जिसका आरंभ फरवरी 2025 में गुवाहाटी में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, असम को भारत के "एक्सप्रेसवे टू आसियान " के रूप में प्रस्तुत करने पर केंद्रित था। क्वालालंपुर में एक सहयोगी रोड शो ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, संभार-तंत्र, सीमा-पार व्यापार और पर्यटन अवसंरचना के क्षेत्र में अवसरों का प्रदर्शन किया।

एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक नर्सिंग कौशल विकास को मजबूत करने और रोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए नर्सिंग प्रतिभा कौशल सहयोग के संबंध में असम सरकार और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना था। असम सरकार ने गुवाहाटी में शहरी नियोजन और सतत शहरी विकास में सहयोग को मजबूत करने के लिए 2023 में शहरी नियोजन के संबंध में सिंगापुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। जून 2026 में सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत सिंगापुर को जी आई-टैग युक्त तेजपुर लीची का पहला

वाणिज्यिक निर्यात आसियान के साथ असम के आर्थिक एकीकरण को प्रगाढ़ करने के सफल प्रयासों का एक उदाहरण है।

सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और बेहतर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी जैसी अवसंरचना की पहलों को उच्च प्राथमिकता दे रही है। बांग्लादेश सरकार को ऋण सहायता (एलओसी) प्रदान की गई हैं और असम के माध्यम से सीमा-पार कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वयित किया जा रहा है।

****